(घ) सरकार इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए कहां तक सहमत हुई है;

(ङ) अब तक क्रियान्वित किए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) शेष सुझावों को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री वाई॰के॰ नायडू): (क) जी हां, पी॰एच॰डी॰ वाणिज्य उद्योग मंडल ने बंजरभूमि विकास हेतु निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए कदम उठाये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) मध्य प्रदेश वाणिज्य उद्योग मंडल से अभी तक कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

Central Grant Under Rural Sanitation Programme in Karnataka

*569. SHRI GUNDAPPA KORWAR: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Karnataka Government has launched a massive campaign for construction of household laterines in rural areas and have incurred as expenditure of Rs. 16.82 crores;

(b) whether the matching grant under the Centrally sponsored Rural Sanitation Programme has been released; if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor and by when it is proposed to be released?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI YERRAN NAIK): (a) Yes, Sir. The State Government of Karnataka is reported to have released Rs. 16.92 crore during the year 1995-96 for own duction of household latrines out of the State's own resources.

(b) the details of Central assistance provided by the Government of India to the State Government of Karnataka under centrally sponsored Rural Sanitation Programme (CRSP) during VIII Five Year Plan were as under:

Year	Amout released (Rupees in Lakhs)
1992-93	90.15
1993-94	127.78
1994-95	256.00
1995-96	1156.72
1996-97 (upto July, 1996)	141.09
TOTAL	1771.74

(c) Outlays of Central assistance under the Centrally Sponsored Rural Sanitation Programme (CRSP) are allocated to various States in accordance with fixed criteria, taking into account incidence of poverty, rural population and difficult areas. The States have to necessarily provide matching contribution under their Minimum Needs Programme (MNP) against Central releases of funds under the CRSP. The States are, however, free to provide more than the required matching contribution under their MNP to widen the coverage as well as to increase the pace of implementation of the rural sanitation programme.

Raid on the Premises of Former Communications Minister

*570A SHRI O. RAJAGOPAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the basis on which the C.B.I. raided the residential premises of the former Communications Minister, Shri Sukh Ram in New Delhi and in Mandi town of Himachal Pradesh;

(b) what are the reasons for not raiding his other houses in Mandi and in Ghaziabad simultaneously;

(c) whether it is a fact that news of the raid at the house in Mandi was leaked out to enable his son to flee the premises with important documents; and

(d) the total amount of unaccounted money recovered?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL. PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) Searches were conducted by the CBI *at* these residential premises of Shri Sukh Ram, former Minister of State, Communications on the basis of search warrants issued by the competent magistrate.

(b) The other houses of Shri Sukh Ram in Mandi and Ghaziabad were not searched simultameoulsy due to lack of information available initially for necessitating search at such places.

(c) No. Sir.

(d) The total amount recovered from Shri Sukh Ram's house from Delhi and Ghaziabad is Rs. 3.61 crores.

मध्य प्रदेश में बंजरभूमि विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन

571. **श्री राधाकिशन मालवीय:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुमोदित बंजरभूमि विकास परियोजना क्रियान्वित की जा रही है,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 से 31 मार्च, 1996 तक सरकार को मध्य प्रदेश के कृषि विभाग से गैर-वानिकी बंजरभूमि विकास संबंधी कितनी परियोजनाएं प्राप्त हुई है और प्रत्येक परियोजना का क्षेत्रफल और उसकी अनुमानित लागत कितनी-कितनी है,

(ग) उक्त परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं सरकार के पास अनुमोदन हेतु लम्बित पड़ी हैं और इनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना-कितना है, और

(घ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (बंजर भूमि विकास विभाग (श्री वाई॰ के नायूडू): (क) जी हां।

(ख) से (घ) वर्ष 1993-94 से 31 मार्च, 1996 तक मध्य प्रदेश सरकार से बंजरभूमि विकास विभाग में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत विचार हेतु 21 परियोजनाऐं प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकार को 9 परियोजनाएं प्रस्ताव में संशोधन करने तथा उन्हें पुनः प्रस्तुत करने हेतु वापस भेज दी गई है। ये राज्य सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं। स्वीकृत तथा लम्बित पड़ी हैं। स्वीकृत तथा लम्बित पड़ी प्रत्येक परियोजना का क्षेत्रफल और कुल लागत का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है।

विवरण-55

स्वीकृत तथा लंबित पड़ी प्रत्येक परियोजना का क्षेत्रफल उसकी कुल लागत का ब्यौरा

क्रमांक	जिला	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	लागत (लाख रुपये में)	अवधि	वर्तमान स्थिति
1.	2	3	4	5	6
1.	भोपाल	922	65.84	1993-94 से 1996-97	स्वीकृत
2.	छिंदवाड़ा	4500	301.69	1993-94 से 1997-98	-वही-
3.	दुर्ग	3680	215.94	1994-95 से 1997-98	-वही-
4.	धार	3000	184.91	1993-94 से 1997-98	-वही-
5.	झबुआ (11)	4980	319.44	1993-94 से 1997-98	-वही-
6.	मांडला	6912	350.20	1993-94 से 1997-98	-वही-
7.	रायगढ़	5700	390.55	1994-95 से 1998-99	-वही-